Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

मुख्यमंत्री 'डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश' और नवाचार युक्त रोलिंग बजट 2026-27 (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

डॉ.मौसमी राय

[1]सहायक प्राध्यापक,गवर्नमेंट एम.एल.बी. गर्ल्स पी.जी. ऑटोनॉमस पी.जी. कॉलेज भोपाल

सारांश :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''मुख्यमंत्री 'डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश' और नवाचार युक्त रोलिंग बजट 2026-27 (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)'' में मध्यप्रदेश के बजट 2026-27 के आलोक में नागरिक सशक्तिकरण के दावों और उनके वास्तविक प्रभावों का विश्लेषण करने का एक प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का यह बजट 'GYANII' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री) के मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है। इस शोध अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के आवंटन में की गई 26 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि और उसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों की समीक्षा करना है। इस शोध में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवंटित 23,883 करोड़ रुपये, सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 हेतु 3,863 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए निर्धारित 1,801 करोड़ रुपये के प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन की कार्यप्रणाली (मेथोडोलॉजी) में प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए उद्देश्यपरक सैंपलिंग और द्वितियक तथ्यों का उपयोग किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश की महिलाओं और शिक्षाविदों से सीधा संवाद स्थापित किया गया। द्वितीयक स्रोतों के रूप में बजट रिपोर्ट, समाचार पत्रों और सरकारी दस्तावेजों का सहारा लिया गया है। इसशोध के परिणाम दर्शाते हैं कि बजट में भारी वित्तीय प्रावधानों से महिलाओं को आर्थिक संबल और आत्मनिर्भरता मिलने की प्रबल संभावना है। निष्कर्षतः, मध्यप्रदेश का 'रोलिंग बजट' मॉडल और नारी शक्ति पर केंद्रित निवेश, राज्य को समृद्ध बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम प्रतीत होता है। यह अध्ययन जांचता है कि क्या ये वित्तीय आवंटन धरातल पर महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने में सक्षम हैं।

मुख्य शब्द :- मध्यप्रदेश, सशक्तिकरण, बजट, GYANII,लाड़ली बहना, रोलिंग बजट

प्रस्तावना :- 18 फरवरी 2026 का दिन मध्यप्रदेश ही नहीं, पूरे देश के इतिहास में अंकित हो गया, जबकि मध्यप्रदेश शासन ने वित्तीय वर्ष के बजट को रोलिंग बजट के रूप में प्रस्तुत किया। मध्यप्रदेश, देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो अमृतकाल 2047 के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और रोलिंग बजट बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का यह बजट 'समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक मध्यप्रदेश' के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी दस्तावेज है। राज्य सरकार ने पारंपरिक बजट प्रणाली से आगे बढ़ते हुए इसे दीर्घकालिक विकास दृष्टि से जोड़ा है, जिससे अगले तीन वर्षों के विकास का ठोस खाका तैयार किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 4,38,317 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प है। विशेष बात यह है कि इस विशाल बजट के बावजूद प्रदेश की जनता पर किसी भी नए कर (Tax) का बोझ नहीं डाला गया है। यह बजट 'GYANII' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री) के छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस बजट के प्रमुख अंशों में किसान कल्याण के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जो कृषि उत्पादन, सुरक्षा चक्र और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करेगा। अधोसंरचना विकास (Infrastructure) के क्षेत्र में प्रदेश के इतिहास में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है, जो औद्योगिक निवेश और बेहतर कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त करेगी। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता 'मुख्यमंत्री लाड़ली

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

बहना योजना' के लिए आवंटित 23,883 करोड़ रुपये से स्पष्ट होती है। इसके साथ ही 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' और 'यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना' जैसे नवाचार बच्चों और माताओं के पोषण व भविष्य को सुरक्षित करेंगे। वहीं, शहरी विकास के लिए 'द्वारका योजना' और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर मालिकाना हक देने की अनूठी पहल इस बजट की विशिष्टता है। युवाओं के लिए कौशल विकास, पीएम श्री महाविद्यालय और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन के क्षेत्र में 'पीएमश्री हेली सर्विस' और वन्यजीव संरक्षण के तहत कूनो में चीता पुनर्स्थापन के प्रयास मध्यप्रदेश को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिला रहे हैं। उधर, आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) 10.69 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18.48 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। साथ ही, प्रति व्यक्ति आय में 9 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी राज्य की बढ़ती आर्थिक सुदृढ़ता का प्रमाण है। अंततः, यह बजट न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की ओर मध्यप्रदेश के कदमों को मजबूती प्रदान करता है।

उद्देश्य :-

1. मध्यप्रदेश के रोलिंग बजट 2026-27 का विहंगावलोकन करके विश्लेषणात्मक अध्ययन करना?
2. बजट में महिलाओं के लिए किये गए प्रावधानों का गहनता से अध्ययन करना?
3. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना योजना के विस्तार का विलेश्षणात्मक अध्ययन करना?

शोध प्रविधि :- उपरोक्त शोध अध्ययन ''मुख्यमंत्री 'डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश' और नवाचार युक्त रोलिंग बजट 2026-27 (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)'' के लिए उद्देश्यपरक (नमूना चयन) सैंपलिंग उपयोग में लाई गई है। प्राथमिक तथ्यों के एकत्रितकरण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके तहत विषय विशेषज्ञों, महिलाएं, वाणिज्य विषयों के जानकार, आम नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि, कॉलेज विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी और जागरूक नागरिकों से संवाद किया गया। इसके साथ ही द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए शोध जर्नल, पुस्तकें, सरकारी रिपोर्ट, विश्वविद्यालयों लाइब्रेरी में आने वाले प्रकाशन, शासकीय रिपोर्ट, समाचार पत्र, टीवी मीडिया रिपोर्ट का अध्ययन किया। इसके पश्चात प्राथमिक एवं द्वितिय तथ्यों का विश्लेषण करके परिणाम निकालकर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

विश्लेषण :- इस शोध अध्ययन ''मुख्यमंत्री 'डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश' और नवाचार युक्त रोलिंग बजट 2026-27 (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)'' के तहत एकत्रित किये गए डाटा के विश्लेषण में यह बात सामने आती है कि मध्यप्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2026—27 का बजट जिसे कि सरकार ने रोलिंग बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, वह प्रशासनिक जरूरतों के साथ ही काफी हद तक सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का मिश्रण है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

Figure 1 : मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मन्त्रि-परिषद की बैठक से पहले, विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2026- 27 के बजट के लिए वित्त विभाग की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

Source : www.mpinfo.org

क्या होता है रोलिंग बजट :-

तीन-वर्षीय खाका: इस बजट में केवल एक वित्त वर्ष (2026-27) के आंकड़े नहीं होते, बल्कि अगले दो वर्षों (2027-28 और 2028-29) के लिए भी सांकेतिक बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं।

निरंतरता और लचीलापन: पारंपरिक स्थिर बजट के विपरीत, रोलिंग बजट को हर साल अपडेट किया जाता है। इसमें पिछले प्रदर्शन और बदलती आर्थिक स्थितियों के आधार पर आगामी वर्षों के अनुमानों में संशोधन किया जा सकता है।

दीर्घकालिक लक्ष्य: इसका उद्देश्य 'विकसित मध्यप्रदेश @2047' के विजन को ध्यान में रखते हुए पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास को एक साल की सीमा से बाहर ले जाकर नियोजित करना है।

वित्तीय अनुशासन: यह व्यवस्था परियोजनाओं में होने वाली देरी और बजट के अभाव में रुकने वाले कार्यों को रोकने में मदद करती है, क्योंकि विभागों के पास अगले तीन साल की वित्तीय उपलब्धता का अनुमान पहले से होता है। संक्षेप में, यह एक गतिशील वित्तीय योजना है जो शासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और भविष्योन्मुखी बनाती है।

इस बजट का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2026-27 के बजट में कुल विनियोग की राशि 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ है। वर्ष के अंत में राजस्व आधिक्य रहना अनुमानित है। पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

बजट 2026-27

बजट का आकार	4 लाख 38 हजार 317 करोड़
कुल राजस्व प्राप्तियां	3 लाख 8 हजार 703 करोड़
राज्य कर एवं करेत्तर राजस्व	1 लाख 42 हजार 61 करोड़
केंद्रीय करों में हिस्सा	1 लाख 12 हजार 137 करोड़
केंद्र से सहायता अनुदान	54 हजार 504 करोड़
पूंजीगत प्राप्तियां	80 हजार 694 करोड़
कुल राजस्व व्यय	3 लाख 8 हजार 658 करोड़
पूंजीगत परिव्यय	80 हजार 266 करोड़
राजस्व आधिक्य	44 करोड़
राजकोषीय घाटा	71 हजार 460 करोड़
जी.एस.डी.पी.	18 लाख 48 हजार 274 करोड़
राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	3.87 प्रतिशत

बजट में प्रतिशत वृद्धि

ग्रामीण विकास विभाग	37 प्रतिशत
नगरीय विकास एवं आवास विभाग	16 प्रतिशत
महिला एवं बाल विकास विभाग	26 प्रतिशत
राजस्व विभाग	43 प्रतिशत
स्कूल शिक्षा विभाग	11 प्रतिशत

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

बजट प्रावधान

स्वास्थ्य के क्षेत्र में	23 हजार 747 करोड़
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	88 हजार 910 करोड़
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए	1 लाख 15 हजार करोड़

प्रमुख योजनाओं में बजट प्रावधान

लाडली बहना योजना	लगभग 23 हजार 800 करोड़
वी.बी.जी. राम जी योजना	लगभग 10 हजार 400 करोड़
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना	लगभग 5 हजार 500 करोड़
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	लगभग 4 हजार 600 करोड़
सिंहस्थ आयोजन	लगभग 3 हजार करोड़

प्रमुख नवीन योजनाओं में बजट प्रावधान

द्वारका योजना	अगले 3 वर्षों में 5 हजार करोड़ का निवेश
स्वामित्व योजना	लगभग 3 हजार 800 करोड़
यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना	700 करोड़

सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाओं में बजट प्रावधान

कुल प्रावधान	1 लाख 83 हजार 708 करोड़
अनुसूचित जनजाति वर्ग	47 हजार 428 करोड़ (कुल प्रावधान का 26 प्रतिशत)

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

अनुसूचित जाति वर्ग	31 हजार 192 करोड़ (कुल प्रावधान का 17प्रतिशत)

जी.एस.डी.पी.

वर्ष 2025-26	16 लाख 69 हजार 750 करोड़
वर्ष 2026-27	18 लाख 48 हजार 274 करोड़

प्रतिबद्ध देयता

ऋण भुगतान	34 हजार 437 करोड़
ब्याज भुगतान	33 हजार 735 करोड़
पेंशन भुगतान	29 हजार 449 करोड़
वेतन भत्ते	लगभग 67 हजार करोड़

कर्ज की स्थिति (अनुमानित)

31 मार्च 2025 की स्थिति	4 लाख 14 हजार 611 करोड़
31 मार्च 2026 की स्थिति	4 लाख 88 हजार 714 करोड़
31 मार्च 2027 की स्थिति	5 लाख 59 हजार 336 करोड़

(31 मार्च 2026 की स्थिति में प्रदेश का कुल कर्ज जी.एस.डी.पी का लगभग 29 प्रतिशत है। जो कि निर्धारित सीमा में है।)

Figure 2 : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा में वर्ष 2026- 27 का बजट प्रस्तुत करने से पहले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा को शुभकामनाएं दीं। Source : www.mpinfo.org

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सिंहस्थ 2028 : सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्रगौरव :- बजट में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोने के लिए विशेष जोर दिया गया है। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए कुल 2,058 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें अकेले संस्कृति विभाग के लिए 1,365 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा अद्वैत दर्शन के वैश्विक प्रचार-प्रसार हेतु ओंकारेश्वर में 'वेदान्त पीठ' की स्थापना (750 करोड़ रुपये) के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य की ऐतिहासिक विरासतों और स्मारकों के संरक्षण के लिए 67 करोड़ रुपये तथा विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों के लिए 65 करोड़ रुपये का आवंटन शासन की 'सांस्कृतिक पुनरुत्थान' की नीति को स्पष्ट करता है। राज्य मंत्री श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी के अनुसार, सिंहस्थ से जुड़े कार्यों के लिए कुल 13,851 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रदेश की छवि को भी निखारेगा।

पर्यटन का वैश्विक विस्तार :- पर्यटन विभाग के लिए आवंटित 566 करोड़ रुपये के माध्यम से मध्यप्रदेश को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसमें पर्यटन अधोसंरचना के लिए 323 करोड़ रुपये का विशेष कोष रखा गया है। खजुराहो को 50 वैश्विक प्रतिस्पर्धी पर्यटन गंतव्यों की सूची में शामिल कर विकसित किया जा रहा है, वहीं ओरछा को "आइकॉनिक पर्यटन स्थल" के रूप में निखारा जाएगा। मालवा और निमाड़ की स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केरियाखेड़ी को 'क्राफ्ट हैंडलूम विलेज' और कुक्षी को 'क्राफ्ट टूरिज्म विलेज' के रूप में विकसित करना ग्रामीण पर्यटन की दिशा में एक अभिनव कदम है।

महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना :- महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में विभाग हेतु 26 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ₹23,883 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹1,801 करोड़ का बड़ा प्रावधान है। बाल कल्याण और पोषण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 हेतु ₹3,863 करोड़ तथा विशेष पोषण आहार के लिए ₹1,150 करोड़ आवंटित हैं। साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए ₹387 करोड़ और आंगनवाड़ी भवनों हेतु ₹337 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। यह बजट 'नारी शक्ति' और 'बाल समृद्धि' के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाने का एक सशक्त प्रयास है।

धार्मिक आस्था और जनजातीय सम्मान :- धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के लिए 127 करोड़ रुपये के प्रावधान में 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' (50 करोड़ रुपये) को निरंतरता दी गई है। शोध का एक महत्वपूर्ण पहलू "जनजातीय देव लोक वनों की संरक्षण योजना" है, जो जनजातीय आस्था के केंद्रों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ती है। 'देवी अहिल्या लोक' और "संस्कृति कल्पवृक्ष यात्रा" जैसे प्रोजेक्ट्स इतिहास को आधुनिकता के साथ सजीव रूप में प्रस्तुत करने का माध्यम बनेंगे।

पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त-घुमंतु समुदाय :- राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा गौर के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विमुक्त-घुमंतु समुदायों के समावेशी विकास हेतु ₹1,691 करोड़ का विशेष प्रावधान करता है। बजट का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षा और कौशल विकास है, जिसमें 'सरदार पटेल कोचिंग योजना' के माध्यम से 4,000 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने और छात्रावासों को 'आदर्श छात्रावास' के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही, पारंपरिक व्यवसायों को आधुनिक बाजार से जोड़ने और विमुक्त समुदायों को छात्रवृत्ति व स्वरोजगार योजनाओं के जरिए मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है, जो सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष :- उच्च शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट सर्व-समावेशी और लोककल्याणकारी है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा, तकनीकी कौशल और आयुष विभाग के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। यह बजट न केवल शिक्षा की गुणवत्ता और भारतीय चिकित्सा पद्धति के विस्तार पर जोर देता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने में भी सहायक सिद्ध होगा, जिससे मध्यप्रदेश एक अग्रणी शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा।

सिंचाई परियोजनाएं :- समृद्ध और सुखद मध्यप्रदेश' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेष रूप से सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए ₹14,742 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है, जो किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट जल प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से अंतिम छोर के किसान तक लाभ पहुँचाने के सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करता है।

मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण :- मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश में 'नीली क्रांति' को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। बजट में विभाग के लिए 412 करोड़ 89 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 70 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के लिए 181 करोड़ और 'मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना' के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित हैं। यह निवेश आधुनिक तकनीक, कोल्ड चेन और मछुआरों के कौशल विकास पर केंद्रित है। दिसंबर 2025 तक 3 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन की उपलब्धि के साथ, यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और मछुआ समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास :- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास का एक सशक्त रोडमैप है। बजट में 'प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना' के लिए 343 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो किसानों को सौर कृषि पंपों के माध्यम से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु 96 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वन संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन:- वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट वन संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए व्यापक वित्तीय प्रावधान करता है। मुख्य आवंटन में कार्यकारी वन वृतों हेतु ₹1,598 करोड़, कैम्पा (CAMPA) के अंतर्गत ₹1,004 करोड़ और कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹699 करोड़ शामिल हैं। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए ₹391 करोड़, राष्ट्रीय उद्यानों हेतु ₹257 करोड़, इमारती लकड़ी उत्पादन हेतु ₹194 करोड़ और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के लाभांश हेतु ₹168 करोड़ निर्धारित हैं। वन्यजीवों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट हेतु ₹139 करोड़ और ग्राम पुनर्वास हेतु ₹150 करोड़ का प्रावधान जनसहभागिता और संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

अनुसूचित जाति कल्याण :- अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट इस वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हेतु समर्पित है। बजट में प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ₹766 करोड़, छात्रावास संचालन हेतु ₹317 करोड़, एकीकृत छात्रावास के लिए ₹167 करोड़ और सीनियर छात्रावास हेतु ₹113 करोड़।वहीं, अत्याचार निवारण राहत योजना के लिए ₹220 करोड़, आवास सहायता हेतु ₹200 करोड़ और ज्ञानोदय विद्यालयों के लिए ₹76 करोड़ का प्रावधान

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु ₹109 करोड़ तथा बस्तियों के विकास के लिए ₹60 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। ये प्रावधान विद्यार्थियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

सुशासन और राजस्व तंत्र का आधुनिकीकरण :- राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा के अनुसार, यह बजट सुशासन और राजस्व तंत्र के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। प्रमुख प्रावधानों में स्वामित्व योजना हेतु ₹3800 करोड़, एसडीआरएफ (SDRF) के लिए ₹2258 करोड़ और उप-संभागीय स्थापना हेतु ₹2098 करोड़ शामिल हैं। साथ ही आपदा राहत, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण और प्रशासनिक अधोसंरचना के लिए भी पर्याप्त आवंटन किया गया है।

जल सुरक्षा और ऐतिहासिक जनस्वास्थ्य :- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके के अनुसार, यह बजट जल सुरक्षा और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से ऐतिहासिक है। इसमें जल जीवन मिशन हेतु ₹4,454 करोड़, ग्रामीण नल-जल संधारण के लिए ₹290 करोड़ और जल प्रदाय गृहों हेतु ₹229 करोड़ का प्रावधान है। ये निवेश हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के संकल्प को सशक्त करेंगे।

किसान कल्याण एवं कृषि विकास :- किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण और कृषि विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। विभाग के लिए ₹31,758 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है, जो कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। विशेष रूप से, वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है। मध्यप्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम और सोयाबीन में देश का 35% योगदान देकर पहले से ही अग्रणी है। अब सरकार का ध्यान मूल्य संवर्धन, पशुपालन और मत्स्य पालन को एकीकृत कर किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर है।

सुगम शिक्षा और परिवहन :- स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार, स्कूल शिक्षा बजट में 11% की वृद्धि की गई है। प्राथमिक शिक्षा हेतु ₹11,444 करोड़ और माध्यमिक शिक्षा हेतु ₹7,129 करोड़ का प्रावधान है। प्रमुख आवंटनों में सांदीपनि विद्यालयों के लिए ₹3,000 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान हेतु ₹5,649 करोड़ और अतिथि शिक्षकों के मानदेय के लिए ₹1,141 करोड़ शामिल हैं। छात्रों के प्रोत्साहन हेतु ₹250 करोड़ के लैपटॉप, ₹100 करोड़ की स्कूटी और ₹210 करोड़ की साइकिलें वितरित की जाएंगी। परिवहन क्षेत्र में ₹230 करोड़ आवंटित हैं, जिसमें 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' के लिए ₹54 करोड़ का प्रावधान है।

'समृद्ध मध्यप्रदेश @2047' के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम :- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार, बजट में सिंहस्थ-2028 की भव्य तैयारियों हेतु ₹3,060 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है। शहरी अधोसंरचना के लिए प्रमुख आवंटनों में नगरीय निकायों को प्रवेश कर हस्तांतरण हेतु ₹3,600 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए ₹2,000 करोड़ और अमृत 2.0 मिशन हेतु ₹1,418 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मेट्रो रेल परियोजना के लिए ₹656 करोड़ और स्थानीय निकायों को 16वें वित्त आयोग के अनुदान स्वरूप ₹2,057 करोड़ दिए गए हैं, जो 'समृद्ध मध्यप्रदेश @2047' के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम है।

स्वास्थ्य के लिए बजट :- उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,747 करोड़ का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है, जो गुणवत्तापूर्ण और किफायती उपचार सुनिश्चित करेगा। मुख्य आवंटनों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु ₹4,600 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए ₹3,056 करोड़ और आयुष्मान भारत योजना के लिए ₹2,139 करोड़ शामिल हैं। जिला एवं सिविल अस्पतालों के लिए ₹2,049 करोड़ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों हेतु ₹1,934 करोड़ का प्रावधान स्वास्थ्य तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

करेगा। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और 'रोलिंग बजट' जैसे नवाचारों के माध्यम से यह बजट समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने का संकल्प प्रस्तुत करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता:- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल के अनुसार, इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ₹23,747 करोड़ का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यह आवंटन स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मंत्री श्री पटेल के अनुसार, समावेशी विकास और जनकल्याणकारी नीतियों के साथ यह बजट प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को अत्याधुनिक बनाकर मध्यप्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

सहकार से समृद्धि' विजन :- बजट में सहकारिता क्षेत्र को 'सहकार से समृद्धि' विजन के तहत मजबूती दी गई है, जिसमें किसानों को शून्य ब्याज पर ऋण हेतु ₹720 करोड़ का ब्याज अनुदान और ₹25,000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

खेलों को प्रोत्साहन :- खेल एवं युवा कल्याण के लिए ₹815 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें 'खेलो इंडिया एमपी' हेतु ₹230 करोड़ और स्टेडियम निर्माण हेतु ₹161 करोड़ शामिल हैं। साथ ही, लाड़ली बहनों के लिए ₹23,882 करोड़ और सिंहस्थ के लिए ₹3,600 करोड़ का विशेष प्रावधान सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक उत्थान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम :- वित्त वर्ष 2026-27 का बजट सामाजिक समावेशन और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त करने वाला है। बजट में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के लिए ₹4,570 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो दिव्यांगों की शिक्षा, पुनर्वास और स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु ₹772 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह निवेश आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और मूल्य संवर्धन पर केंद्रित है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी।

युवा शक्ति कौशल :- बजट युवा शक्ति के कौशल उन्नयन और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। बजट में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए ₹750 करोड़ और पॉलिटेक्निक संस्थाओं हेतु ₹295 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप और सीएम युवा शक्ति योजना हेतु ₹100-100 करोड़ आवंटित हैं। साथ ही, सारंगपुर विधानसभा के अधोसंरचना विकास के लिए ₹135.42 करोड़ की विशेष सौगात दी गई है। यह बजट तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक आवश्यकताओं के बीच समन्वय स्थापित कर 'विकसित मध्यप्रदेश' के लक्ष्य की ओर अग्रसर है।

मिल्क कैपिटल :- बजट मध्यप्रदेश को देश की 'मिल्क कैपिटल' बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बजट में पशुपालन गतिविधियों के लिए ₹2,365 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 'गो संवर्धन योजना' हेतु ₹620.50 करोड़ और 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' के लिए ₹250 करोड़ शामिल हैं। प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत से 46% अधिक है। बजट में 'मुख्यमंत्री वृंदावन योजना' और 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2026-27 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है, जो पशुपालन को व्यावसायिक मजबूती प्रदान करेगा।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

उपभोक्ता संरक्षण कार्यों में तेजी :- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत के अनुसार, बजट 'आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश' के संकल्प को धरातल पर उतारने वाला है। बजट में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए पिछले वर्ष की तुलना में ₹531 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है, जो विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता संरक्षण कार्यों में तेजी लाएगा।

'सर्वहारा वर्ग' के कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण :- ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अनुसार, बजट 'सर्वहारा वर्ग' के कल्याण और ऊर्जा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण को समर्पित है। इस वर्ष ऊर्जा विभाग के लिए ₹33,606 करोड़ का विशाल प्रावधान किया गया है, जो उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करेगा। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए ₹13,914 करोड़ और अटल गृह ज्योति योजना हेतु ₹6,033 करोड़ आवंटित हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 5 एचपी पंपों हेतु निःशुल्क बिजली के लिए ₹5,276 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान है। आर.डी.एस.एस. और ट्रांसमिशन प्रणाली के विस्तार हेतु भी ₹1,791 करोड़ का निवेश किया गया है, जो 'विकसित मध्यप्रदेश' की नींव रखेगा।

निष्कर्ष :- उपरोक्त शोध ‘‘मुख्यमंत्री ‘डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश’ और नवाचार युक्त रोलिंग बजट 2026-27 (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)’’ के तहत उद्देश्यपरक सैंपलिंग और प्राथमिक व द्वितीयक तथ्यों के माध्यम से बजट का मूल्यांकन करने में यह परिणाम सामने आए हैं कि बजट प्रशासनिक कुशलता और सामाजिक संतुलन का सटीक मिश्रण दर्शाता है। यह रोलिंग बजट भविष्योन्मुखी परियोजनाओं में निरंतरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक प्रभावी आर्थिक दस्तावेज है। विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणामों को देखने से पता चलता है कि मध्यप्रदेश का 'रोलिंग बजट 2026-27' अमृतकाल 2047 के लक्ष्यों को समर्पित दस्तावेज है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रस्तुत 4,38,317 करोड़ रुपये का यह बजट 'GYANII' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री) के स्तंभों पर आधारित है। यह बजट 44 करोड़ के राजस्व आधिक्य के साथ संतुलित है। राज्य की GSDP 10.69% की वृद्धि के साथ 18.48 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा 3.87% की नियंत्रित सीमा में है। रोलिंग बजट में अगले तीन वर्षों का वित्तीय खाका तैयार किया गया है। महिला सशक्तिकरण इस बजट का केंद्र है, जहाँ 'लाड़ली बहना योजना' के लिए ₹23,883 करोड़ और महिला एवं बाल विकास विभाग में 26% की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों हेतु ₹3,060 करोड़ का प्रावधान और ओंकारेश्वर में 'वेदान्त पीठ' (₹750 करोड़) की स्थापना आध्यात्मिक विरासत को मजबूती प्रदान करती है। रोलिंग बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को ₹31,758 करोड़ तथा सिंचाई परियोजनाओं को ₹14,742 करोड़ प्रदान कर वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में समर्पित किया गया है। ₹1.83 लाख करोड़ का विशाल हिस्सा सामाजिक उत्थान हेतु आरक्षित है। इसमें अनुसूचित जनजाति (26%) और अनुसूचित जाति (17%) के लिए विशेष आवंटन के साथ छात्रवृत्ति व आवास हेतु भारी निवेश किया गया है। वहीं, राजस्व (43%) और ग्रामीण विकास (37%) शीर्ष पर हैं। शिक्षा क्षेत्र में 11% की वृद्धि के साथ प्राथमिक शिक्षा हेतु ₹11,444 करोड़ और युवाओं के प्रोत्साहन हेतु लैपटॉप व स्कूटी वितरण का प्रावधान है। स्वास्थ्य के लिए ₹23,747 करोड़ तथा ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹33,606 करोड़ का आवंटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करेगा। पशुपालन को ₹2,365 करोड़ देकर राज्य को 'मिल्क कैपिटल' बनाने का लक्ष्य है। बिना किसी नए कर के, यह रोलिंग बजट GSDP में 10.69% वृद्धि सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री ‘डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश’का मार्ग तैयार करते दिख रहा है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
Peer-Peer Reviewed, Refereed & Open Access International Journal - As per UGC Norms
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:5(3), May 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

संदर्भ :-

1. Kothari, C.R. 2004, Research Methodology Methods and Techniques Second Revised Edition
2. Mishra , Dr. Meenu, Pandey, Dr. Prabhat, 2015, Research Methodology: Tools And Techniques
3. गणेशन, एस. एन., 2009, अनुसंधान प्रविधि सिद्धांत और प्रक्रिया
4. शोध विधियां तथा सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद''
5. गुप्ता, उमाकांता, जोशी, वृजरतना, अनुसंधान, स्वरूप और आयाम
6. cmdashboard.mp.gov.in
7. www.mpinfo.org
8. finance.mp.gov.in
9. mpvidhansabha.nic.in
10. mladlibahna.mp.gov.in
11. mpwcdmis.gov.in
12. mpkrishi.mp.gov.in
13. veerbharatnyas.com
14. www.labour.mp.gov.in
15. prd.mp.gov.in
16. mpsedc.mp.gov.in
17. x.com/DrMohanYadav51
18. dharmasva.mp.gov.in
19. www.mptourism.com
20. www.health.mp.gov.in
21. nhmmp.gov.in
22. https://economictimes.indiatimes.com/news/india/madhya-pradesh-budget-2026-27-rs-4-38-lakh-crore-outlay-rs-1-27-lakh-crore-for-womens-schemes/articleshow/128501821.cms?from=mdr
23. https://www.business-standard.com/economy/news/maharashtra-debt-to-rise-by-11-pc-to-touch-rs-9-3-trillion-in-2025-26-economic-survey-126030700867_1.html